[Prof. S. Nurul Hasan]

any excavation or field work in archaeology or anthropology that whatever materials or objects are found are immediately registered in a register which the field team always maintains, giving details like the place from which it has been found and certain other technical details. The hon. Member asked how I could make a definite statement that nothing has gone out. May I, with your permission, read out one sentence from the statement, which reads:

> "Government has no information whether any fossils have been actually taken out of India."

I go by the information that has been given by the Vice-Chancellor and by the co-director who was collaborating with the American team in the work of exploration, and nobody can say that this Indian co-director was in any way in league with any foreign group. In fact, he has been very careful in ensuring that nothing of interest or of value to the expedition or exploration does go out. Therefore, in my opinion the question of making further enquiries does not arise. Until I have some specific information, it would not be proper for me to start any enquiry.

So far as foreign researchers are concerned, a procedure has been prescribed by the Government of India that whenever any foreign researcher comes the relevant academic authority is always consulted, and it is on the advice given by the proper academic authority that the Ministry of Education makes the recommendation that he should be given permission to come and make studies here.

I have already given the reply to the last point raised by my hon. friend that within the means available the universities and other institutions have been supported and are being encouraged to undertake extensive survey and exploration of the fossils.

12.45 hrs.

RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT

ACUTE FOOD SHORTAGE IN MAHARASHTRA

(Interruptions)

MR. SPEAKER: All of you please sit down.

I have received two notices of the following adjournment motions. One is from S/Shri Atal Bihari Vajpayee, S. M. Banerjee and Shyamnandan Mishra, and the motion is:

> "To discuss the explosive situation arising out of the failure of the Central Government to maintain adequate supply of wheat and other foodgrains to the drought hit State of Maharashtra leading to serious food riots in many cities.

The other is from Shri Madhu Limaye and the motion is:

> "The failure of the Centre to enforce the norms laid down in regard to declaration of famine and scarcity areas, and organisation of appropriate relief measures in Maharashtra, Bihar, Gujarat, Mysore, Rajasthan and other States resulting in wide-spread shortages of foodgrains, acute distress, hunger, discontent and shooting of unarmed people by the police such as was witnessed in Sinner in Maharashtra.

It is almost the same.... *(Interruptions)*.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र के विभिन्न भागों और देश के अन्य हिस्सों में भी धन के अभाव से जो गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है उस पर इस सदन को विचार करना चाहिए और विचार करने का तरीका एक ही है कि आप हमारा काम रोको प्रस्ताव स्वीकार करें ? यह मामला महत्वपूर्ण है । अन्न के अभाव को लेकर दंगे हो रहे हैं, लोग दुकानें लूट रहें हैं और सरकार रोटी देने के बजाय गोली दे रही है । मैंने आप से निवेदन किया कि महाराष्ट्र अकालग्रस्त क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र में अन्न की आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है । महाराष्ट्र सरकार ने 26 लाख टन अनाज मांगा था लेकिन केन्द्र ने केवल 14 या 15 लाख टन दिया । हम लोग महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से मिले थे तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां अनाज पैदा नहीं हुआ, यदि केन्द्र अनाज नहीं देगा तो हम लोगों को खाने के लिए कहां से अनाज दे सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि सरकार दावा कर रही है कि हरियाणा, पंजाब में बड़े पैमाने पर अनाज वसूल हो रहा है । वह अनाज अकालग्रस्त क्षेत्रों में, विशषकर महाराष्ट्र में क्यों नहीं पहुंचाया जाता है ? यह सरकार की दूसरी विफलता है ।

तीसरी विफलता यह है कि अगर अनाज बाहर से मंगाने की व्यवस्था की गई है तो उसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ? जब सरकार ने व्यापार अपने हाथ में लिया तो फिर व्यापारियों को दोष देने से काम नहीं चलेगा । हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में और उचित कीमत पर अनाज देने की जिम्मेदारी सरकार की है । (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रस्तावों में बात एक ही है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कालिंग अटेन्शन मोशन एडमिट कर रहें हैं लेकिन उससे काम नहीं चलेगा । हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और उसका आप हमें काम रोको प्रस्ताव स्वीकार करके मौका दीजिए ।

श्री बसंत साठे (अकोला) : आप होलसेल डीलर्स का साथ दे रहें हैं । कन्डेम करने का अधिकार आपको तब तक प्राप्त होता जब इसको कामियाब करने की आप कोशिश करते । (*व्यवधान*)

MR. SPEAKER: So far as the adjournment motion is concerned, if there is any question of law and order, it is a State matter.

So far as the question of food shortage is concerned, we have discussed it a number of times in the House and we have even discussed it during the Debate on the Ministry's Demands on Food & Agriculture only three days back.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But this is a recent occurrence.

अध्यक्ष जी, कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा खत्म हो गई । अब अगर लोग भूख से मरेंगे तो क्या हम लोग चर्चा नहीं उठायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह लाएण्ड आर्डर का प्रश्न है जो स्टेट का मसला है ।

It relates to law and order of the State; it does not relate to us.

If it is a question of shortage of food, we have discussed it a number of times.

However, I am prepared to give you one minute each.

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): On a point of order, Sir.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Mr. Limaye is raising a point of order. It must get precedence over everything else.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): The situation has been pretty disturbing for quite a few days. There seems to be no light down the tunnel.

The Government does not tell us about the exact stock position, and about the supply position. The procurement position also does not seem to be hopeful. In the meantime, people have begun dying and two starvation deaths of Adivasis have been reported this morning, and in Maharashtra there have been food riots all over, in many parts. I ask you.... (*Interruptions*). Is this the discipline they want to establish in the House? I ask you: what are we doing to attract these remarks from them? .... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I appeal to you all that certain decorum should be maintained. Please sit down.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, क्या यह बात नहीं करने दगे ?

SHRI VASANT SATHE: Have you condemned the hoarders? On the one side you take the side of the hoarders and on the other you talk in the name of the people..... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Please sit down. Please do not interrupt him. After all they have given their motions. Let me listen to them.... (*Interruptions*).

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप अपनी बात कहिये, हम अपनी बात कहेंगे । मगर यह टोका टाकी नहीं चलेगी । गलत बात कौन है इस का फैसला कौन करेगा ?

श्री मधु लिमये । अध्यक्ष जी, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय : जिस आर्डर में नोटिस आये हैं उसी आर्डर में बुला रहा हूं । आप को भी सुन लूंगा ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: You are not able to protect me from these persons.... (*Interruptions*).

My submission is that the situation is so serious that the House must immediately proceed to discuss it. There can be no justification for delaying a discussion of this important matter and of this grave situation. I would, therefore, crave your indulgence for permitting us to discuss the subject right now.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता था कि यह तर्क करने की और बहस करने की जगह है । लेकिन आज मुझे नया सबक मिल रहा है । अध्यक्ष महोदय, तर्क किया था, गाली नहीं (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय मैं यह जानता हूं कि स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार करना या न करना आप के विवेक की बात है । लेकिन अध्यक्ष का विवेक भी नियमों से निश्चित होता है, तय होता है । इसलिए मैं आशय पर नहीं बोलूंगा, मैं केवल यह अर्ज करना चाहूंगा.....

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): I am challenging his right to speak on the Motion which he has given. I rise on a point of order.

MR. SPEAKER: I have examined everything. There is no point of order.

SHRI C. M. STEPHEN: Before taking oath he must not enter upon the duties as a Member. He took oath only today. He gave notice before he took oath. He should not exercise his duty as a Member before taking oath.

MR. SPEAKER: I have examined it. The Member can give notice. It is only after the oath that he has given notice. Please resume your seat.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, पहले स्पीकर कौन है इस का निर्णय हो । अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि मैं यह जानता हूं कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करना या न करना आप के विवेक की बात है । लेकिन अध्यक्ष का विवेक भी नियमों में मर्यादित होता है, तय होता है । इसलिये मैं आशय पर नहीं बोलूंगा, मैं केवल यह अर्ज करूंगा कि मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है नियम के अनुसार कैसे है ? यदि आप को मेरी बात जंचे तो उस के ऊपर पुनर्विचार करें, नहीं जंचे तो ठुकरा दीजिये .....

अध्यक्ष महोदय : पोइंट आफ आर्डर क्या है ? अगर आप अपने प्रस्ताव पर कहना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन पौइंट आफ आर्डर इस वक्त क्या है ?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय स्टीफन ने जो अधिकार के बारे में कहा कि मुझे अधिकार नहीं है, उस बात को साफ करना चाहता हूं कि मुझे नोटिस देने का अधिकार है कि नहीं.. (व्यवधान) आप को अक्ल नहीं है तो बैठ जाइये । आप अध्यक्ष नहीं हैं जो तय करें । कल इंदिरा माई की कृपा हो जायेगी तो आप भी बन जाइयेगा । . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पाइंट आफ आर्डर तो नहीं है, आप का सबमिशन जरूर है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, 1965–66 में .... (व्यवधान)

13 hrs.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप ऐसा मत कीजिये, मुझे उनको सुन लेने दीजिये ।

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मैं दो मिनट उन को सुनना चाहता हूं । आप ने इतना समय जाया कर दिया, इतने में तो मैं उन को सुन लेता ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, 1965–66 में यहां जो बहस हुई उस के फलस्वरूप उस समय के खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने केन्द्र से यह निर्देश दिया था कि जिन इलाकों में फसल 75 प्रतिशत, रुपये में 12 आना मारी गयी है, उस इलाके को अकाल क्षेत्र घोषित करना चाहिये । केन्द्र से निर्देश गया है । अगर माननीय सुब्रह्मण्यम, हमारे पुराने मित्र सदन में होते तो वह कहते, इस बात को कोई काट नहीं सकता । 75 प्रतिशत फसल यदि मारी जाती है तो उस इलाके को अकाल क्षेत्र घोषित किया जायगा, यह केन्द्र का निर्देश है ।

खाद्य का वितरण संविधान की दो धाराओं से नियंत्रित होता है । संविधान के अनुच्छेद 302, जिसमें अन्तर्राज्यीय व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है । यह राज्य का मामला नहीं है । अनुच्छेद 302 को देखिये । आप पायेंगे कि पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार को वह नियंत्रित करे । और खाद्य यह अन्तर्राज्यीय व्यापार का विषय है, उस के बिना ठीक वितरण नहीं होगा ।

तीसरी बात यह है कि खाद्यान्न विदेश से मंगाया जाता है और अनुसूची 7 की केन्द्रीय फेहरिस्त में यदि देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि आयात निर्यात व्यापार

Trade & Commerce with foreign countries; Import & Export across customs frontier; Definition of customs frontier.

[श्री मधु लिमये]

अध्यक्ष महोदय, इसलिये आयात का काम भी केन्द्रीय सरकार और पार्लियामेंट के अधीन आता है । इसलिये जो विषय मैंने उठाया है अकाल के बारे में केन्द्रीय सरकार के जो निर्देश हैं उन का पालन माननीय शिन्दे और माननीय फखरुद्दीन अली अहमद ने नहीं करवाया है । दूसरे खाद्य वितरण का विषय केन्द्र के अधीन आता है । खाद्य वितरण ठीक से नहीं किया गया, और चूंकि आयात करने का काम भी यही करते हैं, इन की यह जिम्मेदारी है । जो गोली चली इन की गलत नीतियों का केवल नतीजा मात्र है । मैं नतीजे पर नहीं बोल रहा हूं, जो कारण हैं असफलता के वह मैं बता रहा हूं, और यह केन्द्रीय सरकार की असफलता है ।

इसलिये मैंने साबित किया है कि यह जो स्थगन प्रस्ताव है वह नियम के अनुकूल है, आप मेहरबानी कर के इस पर पुनर्विचार करें । यदि आज निर्णय नहीं देना चाहते हैं तो कल दीजिये ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): In my adjournment motion, I have raised the question of Government's failure because of inadequate supply of foodgrains to the State of Maharashtra. This has resulted in demonstration and the police have killed four persons and injured about 25 persons.

The other day when this question was raised, I said that there was a serious situation in Nagpur, Kamptee and Malegaon. Those leaders who were condemning the conspiracy between the hoarders and the bureaucrats have been arrested under the DIR. I was surprised to learn this. I had presided over a meeting on the 17th and the meeting was addressed by me and another leader. We were surprised to learn that one Mr. Ganguli and another one Mr. Deshkar had been arrested. This is surprising. Actually, the shops were not looted, but they had unearthed nearly 30 to 40 bags of wheat. Then, the commissioner came there, and unfortunately, instead of seizing the stocks, he arrested those persons. This is a matter of shame.

My submission is only this that this is a fit case for adjournment motion, and a fit case to censure the Central Government on an adjournment motion on two counts, firstly, inadequate supply of foodgrains and secondly failure to ensure the issue of necessary directives to the State Government in view of the famine conditions in the State of Maharashtra.

I would like to impress on the hon. Minister and my other hon. friends that there is a deep-rooted conspiracy between the hoarders and the bureacrats, or *nagarsheths* and *naukarshahis*. They are united together to sabotage the policy of foodgrains takeover. Instead of being shot down, those hoarders are still at large. The people wanted food, but they got bullets, while those who were hoarding are still at large. I would request Government to release those arrested and to see that these hoarders are arrested immediately. Otherwise .....

MR. SPEAKER: May I tell him that I do realise that this is a very important matter. I quite appreciate that it is an important matter, but on this very subject, in this very session, we had a number of discussions and short-duration discussions also.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not allowing it, Mr. Piloo Mody. You can raise it at some other time, not now.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: That is not part of the motion which is before me now.

That is not involved in the motion before me. So, why is he raising it now? His name is also not there.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप फैसला देने में जल्दी मत कीजिये । हम ने इस सवाल पर पहले चर्चा कर ली है इसलिये स्थगन प्रस्ताव मंजूर न किया जाय यह तर्क गले के नीचे नहीं उतरेगा। जो घटनायें घटी हैं वे नयी घटी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस हाउस में दो, तीन दफा इस पर और ड्राउट पर बहस हो चुकी है । अभी दो दिन हुए ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स पर डिस्कशन हुआ ।

और अगर आप चाहते हैं कि ला ऐंड आर्डर पर डिस्क्शन हो तो वह स्टेट का मसला है । हर पहलू पर दो दिन पहले बहस कर चुके हैं इसलिये यह मसला ऐडजर्नमेंट का विषय कैसे हो सकता है ?

But I can allow the calling-attention motion, which I have already allowed. I am very sorry that I cannot give my consent to the adjournment motion. This has been discussed a number of times.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब इस पर पहले चर्चा हो चुकी है, तो फिर कालिंग एटेन्शन नोटिस की भी क्या जरुरत है ? आप ने फांसिल्ज पर चर्चा करने के लिए एक घंटा दे दिया, लेकिन जब लोग भूखों मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और देश में अराजकता फैल रही है, तो आप उस के बारे में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देते हैं ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Human beings have to be reduced to fossils and then it would be discussed here!

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Under this benign Government.

MR. SPEAKER: Shri Raj Bahadur.

13.11 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF CENTRAL INLAND WATER TRANSPORT CORPORATION LTD., CALCUTTA

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Review by the Government on the working of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Calcutta, for the year 1971-72.

(ii) Annual Report of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Calcutta, for the year 1971-72 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See* No. LT-4847/73].

NOTIFICATIONS UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHR ANNASAHEB P. SHINDE): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:—

(i) The Fertilizer (Control) First Amendment Order, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 176(E) in Gazette of India dated the 24th March, 1973.

(ii) The Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No.